



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 7 अप्रैल, 2005/17 चैत्र, 1927

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171 004, 7 अप्रैल, 2005

संख्या वि० स० विधायन-गवर्नमेंट बिल/1-29/2005.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र

विकास कर विधेयक, 2005 (2005 का विधेयक संख्यांक-13) जो आज दिनांक 7 अप्रैल, 2005 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

जे० आर० गाज़टा,
सचिव,
हि० प्र० विधान सभा ।

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र विकास कर विधेयक, 2005

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य के किसी स्थानीय क्षेत्र में उपयोग या विक्रय के लिए मोटर यान तथा उसमें उपयोग या उपभोग के लिए अन्य माल के प्रवेश पर कर का उद्ग्रहण और संग्रहण करने तथा उनसे सम्बद्ध या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2005 है ।

संक्षिप्त नाम
और
प्रारम्भ ।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ परिभाषाएं । के विरुद्ध न हो,--

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है ;

(ख) "निर्धारिती" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन कर संदेय है;

(ग) “किसी स्थानीय क्षेत्र में माल लाना” से अभिप्रेत है, स्थानीय क्षेत्र के भीतर इसको लाते हुए स्थानीय क्षेत्र में माल का प्रवेश कराना या स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से स्थानीय क्षेत्र के भीतर इसका लाया जाना ;

(घ) “किसी स्थानीय क्षेत्र में मोटर यान लाना” से अभिप्रेत है, स्थानीय क्षेत्र के भीतर इसको लाते हुए स्थानीय क्षेत्र में मोटर यान का प्रवेश कराना या स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से स्थानीय क्षेत्र के भीतर इसका लाया जाना;

५२ ५ B d k j c k j B में सम्मिलित है,—

(i) कोई व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, संकर्म संविदा, पट्टे पर देना या व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, संकर्म संविदा या पट्टे पर देने के स्वरूप कोई प्रोद्यम या समुत्थान चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, संकर्म संविदा, पट्टे पर देना, प्रोद्यम या समुत्थान, नियमित रूप से और अभिलाभ या लाभ के आशय से चलाये जाते हैं या नहीं और चाहे उससे कोई लाभ प्रोद्भूत होता है या नहीं; और

(ii) ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, संकर्म संविदा, पट्टे पर देने, प्रोद्यम या समुत्थान के सम्बन्ध में या उसके आनुषंगिक या प्रासंगिक कोई संव्यवहार है ;

(च) “आयुक्त” से हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर 2005 का 12 अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त आयुक्त अभिप्रेत है ;

(छ) “किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश” से, राज्य से बाहर किसी स्थान से किसी स्थानीय क्षेत्र में या राज्य में किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी स्थान से माल को ले जाना या लाना अभिप्रेत है ;

(ज) “किसी स्थानीय क्षेत्र में मोटर यान के प्रवेश” से इसके सभी व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित, मोटर यान का,

किसी स्थानीय क्षेत्र में, इसके बाहर के किसी स्थान से उसमें उपयोग या विक्रय के लिए, प्रवेश अभिप्रेत है ;

(झ) “माल” से सभी प्रकार की जंगम (चल) सम्पत्ति अभिप्रेत है और पशुधन भी इसके अन्तर्गत है ;

(ज) “माल वाहक” से माल के यातायात का किसी भी प्रकार का यान अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत पाइप लाइन, मोटर यान, नौका, ठेला गाड़ी, पशु द्वारा चलाये जाने वाले छकड़े, ट्रैक्टर-ट्रेलर और इसी प्रकार के अन्य भी सम्मिलित हैं;

(ट) किसी आयातकर्ता के सम्बन्ध में समय अवधि के सन्दर्भ में प्रयुक्त “सकल आवर्त” से माल का संकलित मूल्य जिसे आयातकर्ता दी गई अवधि के दौरान किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल की प्रविष्टि पर लाता है या प्राप्त करता है, अभिप्रेत है ;

(ठ) “आयातकर्ता” से आकस्मिक आयातकर्ता सहित, कोई भी व्यक्ति, जो कारबार के अनुक्रम में, चाहे अपनी ओर से या किसी प्रमुख (प्रिंसीपल) की ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी माल को लाता है या प्राप्त करता है या किसी स्थानीय क्षेत्र में उसके प्रवेश पर किसी माल को प्राप्त करने का हकदार है, अभिप्रेत है ; और इसमें कोई आकस्मिक आयातकर्ता सम्मिलित है;

स्पष्टीकरण.—जब कोई परेषिती, किसी माल का स्थानीय क्षेत्र में इसके प्रवेश पर परिदान नहीं लेता है और ऐसा माल किसी विधि के उपबन्धों के अधीन विक्रीत कर दिया जाता है तो वह क्रेता जो विक्रय किए जा रहे ऐसे माल का परिदान लेता है, उसका आयातकर्ता समझा जाएगा।

(ड) “मोटर यान का आयातकर्ता” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से किसी स्थानीय क्षेत्र में उसमें उपयोग अथवा विक्रय के लिए कोई मोटर यान लाता है और जो

स्थानीय क्षेत्र में इसके प्रवेश के समय मोटर यान को रखता है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित है जो मोटर यान - 1988 का 59 अधिनियम, 1988 के अधीन राज्य में इसके रजिस्ट्रीकरण के समय पर मोटर यान रखता है ;

(ढ) “स्थानीय क्षेत्र” से हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 का 12 1994 के अधीन स्थापित नगर निगम, या हिमाचल प्रदेश नगरपालिका 1994 का 13 अधिनियम, 1994 के अधीन स्थापित नगरपालिका, या छावनी 1924 का 2 अधिनियम, 1924 के अधीन स्थापित छावनी बोर्ड, या हिमाचल 1994 का 4 प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अधीन गठित किसी, अन्य स्थानीय निकाय के अन्तर्गत क्षेत्र, या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित या बने रहने वाले किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण की, सीमाओं के भीतर कोई क्षेत्र या राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार अधिसूचित कोई अन्य क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(ण) “विनिर्माता” से कोई व्यक्ति जो पूर्णतः या भागतः माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण कारबार चलाता है, अभिप्रेत है ;

1988 का 59 (त) “मोटर यान” से मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी कोई यान अभिप्रेत है ;

(थ) “कारबार का स्थान” से अभिप्रेत है कोई स्थान जहां पर कोई आयातकर्ता कारबार कर रहा है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है,—

- 1988 का 59
- (i) कोई वेयरहाउस, गोदाम या अन्य स्थान जहां पर आयातकर्ता अपने माल का भण्डारकरण और प्रसंस्करण करता है;
 - (ii) कोई स्थान जहां पर आयातकर्ता माल का उत्पादन या विनिर्माण करता है;
 - (iii) कोई स्थान जहां आयातकर्ता अपनी लेखा बहियां रखता है;

(iv) कोई स्थान जहां आयातकर्ता किसी अधिकर्ता (चाहे किसी नाम से पुकारा जाए) के माध्यम से कारबार चलाता है, ऐसे अधिकर्ता के कारबार का स्थान;

(द) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ध) "मोटर यान का क्रय मूल्य" से बीजक से यथा अभिनिश्चित मोटर यान का मूल्य और जिसमें किसी यान से लगे उप-साधनों का मूल्य, बीमा, आबकारी शुल्क, प्रतिशुल्क, विक्रय कर, परिवहन फीस, दुलाई प्रभार और किसी मोटर यान के क्रय पर उद्ग्रहणीय सभी अन्य आनुषंगिक प्रभार सम्मिलित है, अभिप्रेत है :

परन्तु यदि किसी मोटर यान का क्रय मूल्य, बीजक की अप्रस्तुतिकरण या आप्राप्यता के कारण अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है, या जब प्रस्तुत किया गया बीजक गलत साबित हो जाता है या क्रय से अन्यथा यदि मोटर यान उपार्जित या प्राप्त किया जाता है, तब किसी मोटर यान का क्रय मूल्य, मोटर यान का बाजार मूल्य होगा ।

(न) "किसी माल की प्राप्ति" से किसी माल का परिदान या कब्जा लेना, चाहे वह वास्तविक या रचनात्मक है, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल को प्राप्त करवाना अभिप्रेत है;

(प) "विक्रय कर" से यथास्थिति, केन्द्रीय विक्रय कर 1956 का 74 अधिनियम, 1956 और हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 का 12 2005 के अधीन उद्ग्रहणीय कर अभिप्रेत है;

(फ) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ब) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(ध) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(म) "कर से" इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर अभिप्रेत है;

(य) "कर योग्य माल" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न माल अभिप्रेत है;

(यक) किसी निर्धारिती के सम्बन्ध में प्रयुक्त "आवर्त" से अभिप्रेत है ऐसे माल के मूल्य का पूर्णयोग जो निर्धारिती किसी दी गई अवधि के दौरान उपभोग या उपयोग के लिए किसी स्थानीय क्षेत्र में लाता है या प्राप्त करता है और जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार अवधारित किया जाता है;

(यख) "माल के मूल्य" से अभिप्रेत है ऐसे माल का क्रय मूल्य अर्थात् क्रय मूल्य जिस पर कोई आयातकर्ता, परिवहन, पैकिंग, अग्रेषण और संभालने के प्रभार कमीशन, बीमा, कर, शुल्क और इसी प्रकार के अन्य, की लागत के रूप में उस द्वारा वहन किए गए प्रभारों को शामिल करते हुए, माल का क्रय करता है या यदि उसके द्वारा ऐसे माल का क्रय नहीं किया गया है तो स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल का प्रचलित (विद्यमान) बाजार मूल्य;

(यग) "संकर्म संविदा" से,--

- (i) किसी भवन, सड़क, पुल या किसी अन्य जंगम संपत्ति का सन्निर्माण, सुसज्जा, सुधार, रखरखाव या मरम्मत, या
- (ii) किसी जंगम सम्पत्ति का विनिर्माण, प्रसंस्करण, फ्रेब्रिकेशन, परिनिर्माण, संस्थापन सुसज्जा, सुधार, परिवर्तन, मरम्मत, संपरिवर्तन, कमीशनिंग कार्यान्वित करने के लिए, नकदी आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए कोई करार अभिप्रेत है ;

(यघ) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।

अध्याय-2

कर का उद्ग्रहण

3. (1) अनुसूची में विनिर्दिष्ट के सिवाय, स्थानीय क्षेत्रों में समस्त कर का प्रकार के माल के प्रवेश पर, उसमें उपभोग या उपयोग के लिए, ^{उद्ग्रहण ।}
 2005 का 12 हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन उद्ग्रहणीय कर की दरों से अनधिक ऐसी दरों पर, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकेगी, कर उद्ग्रहीत और संगृहीत किया जायेगा और विभिन्न माल या माल के विभिन्न वर्गों या विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों की बावत विभिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत कर आयातकर्ता द्वारा संदत्त किया जायेगा:

परन्तु कोई आयातकर्ता तब तक कर के संदाय के लिए दायी नहीं होगा जब तक कि कराधेय माल, जिसे वह किसी स्थानीय क्षेत्र में लाता है या उसमें उनके प्रवेश पर प्राप्त करता है, का संकलित मूल्य एक वर्ष में बीस लाख रुपये या ऐसी अन्य राशि, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे,से अधिक नहीं हो जाता है:

परन्तु यह और भी कोई आयातकर्ता जो इस अधिनियम के अधीन कर संदाय करने का एक बार दायी हो जाता है, तीन क्रमवर्ती वर्षों के अवसान तक इस प्रकार लगातार दायी रहेगा, जिसमें से प्रत्येक वर्ष के दौरान किसी कराधेय माल जिसे वह किसी स्थानीय क्षेत्र में लाता है या उसमें उसके प्रवेश पर प्राप्त करता है, का संकलित मूल्य, प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट राशि से, अधिक नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण.—जहां माल आयातकर्ता से विभिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में इसके प्रवेश पर प्राप्त किया जाता है, तो आयातकर्ता, यदि कोई हो, जो आगे ऐसे व्यक्ति से माल प्राप्त

करता है, स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर माल प्राप्त किया गया समझा जायेगा ।

(3) कर ऐसी रीति में उद्गृहीत, निर्धारित और संगृहीत किया जायेगा, जैसी विहित की जाए ।

(4) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन 2005 का 12 रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा आयात किए गए अधिसूचित माल पर कोई कर उद्गृहीत नहीं किया जायेगा, जो किसी स्थानीय क्षेत्र के भीतर राज्य में पुनःविक्रय के प्रयोजन के लिए या अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में ऐसा माल लाता है:

परन्तु यदि कोई ऐसा व्यौहारी पुनःविक्रय के प्रयोजन के लिए अधिसूचित माल आयात करने के पश्चात्, ऐसे माल का उपभोग किसी अन्य रूप में या इसे पुनःविक्रय के सिवाय किसी अन्य रीति में ऐसे माल का व्यौहार करता है तो वह तुरन्त निर्धारण प्राधिकारी को सूचित करेगा ।

मोटर यानों
पर कर के
उद्ग्रहण के
विशेष
उपबंध ।

4. (1) इस अधिनियम की धारा 3 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी स्थानीय क्षेत्र में वहां के उपयोग या विक्रय के लिए किसी मोटर यान के प्रवेश पर कर उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा:

परन्तु ऐसा मोटर यान राज्य में रजिस्ट्रीकरण के लिए या नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (मार्क) समनुदेशित करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन दायी होगा:

1988 का 59

परन्तु यह और कि उस मोटर यान की बावत जो उस तारीख से पूर्व जिसको यह उस अधिनियम के अधीन राज्य में रजिस्ट्रीकृत

1988 का 59 किया जाता है, से पन्द्रह मास या अधिक अवधि के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन किसी राज्य क्षेत्र या किसी अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत किया गया था, से कोई कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा ।

(2) मोटर यान के क्रय मूल्य पर उद्गृहीत कर राज्य में लागू विक्रय कर दर तथा यान के क्रय से सम्बन्धित बीजक में मोटर यान के विक्रय पर प्रभारित विक्रय कर या केन्द्रीय विक्रय कर के बीच के अन्तर के बराबर की दर पर होगा :

परन्तु इस धारा के प्रयोजन के लिए राज्य में लागू विक्रय कर दर मोटर यान के क्रय से सम्बन्धित बीजक में वर्णित तारीख से ली जाएगी:

परन्तु यह और कि यदि मोटर यान के क्रय के सम्बन्ध में कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है या यदि बीजक यथास्थिति, प्रभारित विक्रय कर या केन्द्रीय विक्रय कर की दर नहीं दर्शाता है तब इस धारा के अधीन लागू कर की दर निर्धारण की तारीख से राज्य में लागू विक्रय कर की दर होगी ।

5. जहां कोई व्यक्ति किसी मोटर यान को मोटर यान कतिपय परिस्थितियों में कर की छूट ।
1988 का 59 अधिनियम, 1988 के अधीन किसी संघ राज्य क्षेत्र या किसी अन्य राज्य में इसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए किसी स्थानीय क्षेत्र में लाता है और ऐसा प्रवेश राज्य में, ऐसे संघ राज्य क्षेत्र या राज्य से उसके निवास के स्थान के बदलने के परिणाम स्वरूप हुआ है तो आयुक्त, इस सम्बन्ध में उसे किए गये आवेदन पर लिखित में आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को इस सम्बन्ध में, सबूत के प्रस्तुत करने के अध्याधीन, ऐसे यान के प्रवेश पर, प्रवेश कर के संदाय से छूट दे सकेगा ।

6. प्रत्येक आयातकर्ता जो इस अधिनियम की धारा 3 की रजिस्ट्रीकरण। उपधारा (2) के अधीन कर संदत्त करने का दायी है, ऐसी रीति में,

ऐसी फीस के संदाय और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी होगा :

परन्तु यह कि यदि ऐसा आयातकर्ता, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तो वह, इस 2005 अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा ।

अध्याय-3

कर की विवरणियाँ, निर्धारण, संदाय, वसूली तथा संग्रहण

सकल
आवर्त से
कटौतियाँ ।

7. (1) किसी अवधि के लिए कर के लिए दायी आवर्त की संगणना करते समय, कोई आयातकर्ता उस अवधि के दौरान क्रय किए माल के अपने सकल आवर्त में से निम्नलिखित कटौती कर सकेगा:-

(क) अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल का मूल्य;

(ख) माल का मूल्य जो उपयोग अथवा उपभोग किए बिना स्थानीय क्षेत्र के बाहर परित्यक्त किया गया है;

(ग) माल का मूल्य जो चाहे ऐसे रूप या किसी अन्य रूप में इस अधिनियम के अधीन एक बार कर के अध्याधीन कर दिया गया है;

(घ) माल का मूल्य जिस पर राज्य को विक्रय कर का संदाय कर दिया गया या संदेय हो गया है ;

(ङ) माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग हेतु पट्टे पर लिए गए या प्राप्त किए गए सन्यंत्र, मशीनरी, उपकरण तथा औजारों का मूल्य;

(च) पुनःविक्रय या उपयोग हेतु स्थानीय क्षेत्र में लाए गए या प्राप्त माल का मूल्य, चाहे ऐसे रूप या भिन्न-भिन्न रूप में स्थानीय

क्षेत्र में उसके पास पड़ा है सिवाय जब इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया जाता है :

परन्तु इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कर लिया जाता है, के सिवाय, इस खण्ड के अधीन कटौती किए गए माल का मूल्य तुरन्त उत्तरवर्ती अवधि के लिए आवर्त का भाग रूप होगा :

परन्तु यह और की संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और औजारों का मूल्य, यदि आवर्त का भाग है, लूजिंग स्टॉक माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग हेतु का भाग रूप हो सकेगा, यदि पूंजीकृत (कैप्टलाइज्ड) हो; तथा

(छ) ऐसे अन्य माल का मूल्य जो विहित किया जाए ।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए केवल ऐसे माल के मूल्य की कटौती अनुज्ञेय होगी जो आयातकर्ता के सकल आवर्त का भाग रूप है और यदि कतिपय माल के मूल्य की कटौती एक खण्ड के अधीन की गई है, तब किसी अन्य खण्ड के अधीन इसकी कटौती नहीं की जाएगी ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन दावाकृत कटौतियां, ऐसे सबूत के, ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में प्रस्तुतीकरण के अधीन रहते हुए होगी जो विहित की जाए । निर्धारण प्राधिकारी, प्रस्तुत किये गए सबूत की मौलिकता तथा शुद्धता के बारे में अपने समाधान के लिए किसी सुसंगत साक्ष्य की मांग कर सकेगा ।

8. इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन, व्याहारी द्वारा संदेय किसी ब्याज या शास्ति सहित कर का निर्धारण, पुनर्निर्धारण, संग्रहण और संदाय प्रवर्तित करने के लिए तत्समय सशक्त प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किसी आयातकर्ता

प्राधिकारी
और कर का
प्रशासन ।

द्वारा संदेय किसी ब्याज या शास्ति सहित कर का निर्धारण, पुनर्निर्धारण, संग्रहण, संदाय और प्रवर्तन करेंगे, मानों कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे आयतकर्ता द्वारा संदेय कर या ब्याज या शास्ति, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन कर है और इस प्रयोजन के लिए वे समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जो उनकी, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन है और रजिस्ट्रीकरण, प्रतिभूति, कर के संदाय और विवरणियों, ब्याज के संदाय, कतिपय मामलों में कर के संग्रहण के विरुद्ध प्रतिषेध, कर के निर्धारण, कर का पुनर्निर्धारण, कर के निर्धारण या पुनर्निर्धारण की पूर्णता के लिए परिसीमा का लागू न होना, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय कर और शास्ति, कर, शास्ति और ब्याज का सम्पत्ति पर प्रथम प्रभार होना, वसूली का विशेष ढंग, प्रतिदाय, लेख, उत्पादन और बहियों, दस्तावेजों और लेखों का निरीक्षण, सर्वेक्षण, जांच पड़ताल नाके और बैरियर की स्थापना और अभिवहन में माल का निरीक्षण और माल के वाहक और परिवहन कम्पनियों के अधिकर्ता, निर्धारितियों इत्यादि द्वारा विवरणियों के रजिस्ट्रीकरण करेंगे और प्रस्तुत करने, जो प्राधिकृत अधिकर्ता के माध्यम से हाजिर होने को अनुज्ञात हो, सूचना मंगवाने की शक्ति, शक्तियों का प्रत्यायोजन, कारबार का अन्तरण, विभक्त हिन्दू परिवार, विघटित फर्मों इत्यादि द्वारा कर के संदाय का दायित्व, विधिक वारिसों का कर संदत्त करने का दायित्व, कतिपय कार्यवाहियों का वर्जन, अपील, पुनरीक्षण, भूलों की परिशुद्धि, उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण, प्राधिकारियों की शपथ पर साक्ष्य लेने की शक्ति, अपराध और शास्तियाँ, अपराधों का शमन, अपराधों का संज्ञान, व्यतिक्रमी कम्पनियों के निदेशकों का कर संदत्त करने को दायी होना, कतिपय सम्पत्ति का व्ययन, परित्राण (इन्डमैनिटी) इत्यादि का गोपनीय होना, नियुक्त व्यक्तियों का लोक सेवक होना, पुलिस और अन्य अधिकारियों से सहायता प्राप्त करने की शक्ति और सबूत के भार सहित उस अधिनियम के समस्त उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

(2) उप-धारा (1) के उपबन्धों के अधधीन, व्यौहारी से अन्यथा किसी आयातकर्ता की दशा में, कर का निर्धारण, संदाय, प्रवर्तन और संग्रहण ऐसा होगा, जैसा विहित किया जाए ।

2005 का 12 (3) अपराध और शास्तियों (किसी अपराध के लिए अभियोजन के बदले में शास्ति से सम्बन्धित उपबन्धों सहित या किसी अपराध के लिए शास्तियों या दण्ड के अतिरिक्त) से सम्बन्धित समस्त उपबन्ध और हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के, ब्याज के उद्ग्रहण या प्रभरण से सम्बन्धित उपबन्ध आवश्यक उपान्तरणों सहित इस अधिनियम के अधीन संदत्त करने को अपेक्षित किसी कर के निर्धारण, पुनर्निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन के सम्बन्ध में और संदाय के ऐसे निर्धारण, पुनर्निर्धारण, संग्रहण, प्रवर्तन से सम्बन्धित किसी प्रक्रिया के सम्बन्ध में लागू होंगे मानो कि इस अधिनियम के अधीन कर हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन कर था ।

9. (1) राज्य सरकार, यदि उसकी राय में लोक हित में राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक है, अधिसूचना द्वारा और ऐसे निर्बन्धनों तथा की कर से शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी अवधि के लिए जो अधिसूचना कट्ट देने और में विनिर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम के अधीन आयातकर्ताओं के कमी करने की शक्ति। किसी वर्ग द्वारा देय कर में छूट प्रदान कर सकेगी या कम कर सकेगी।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी निर्बन्धन या शर्त का, किसी आयातकर्ता द्वारा उल्लंघन किया जाता है या अनुपालन नहीं किया जाता है अथवा उसमें अधिरोपित किसी शर्त अथवा निर्बन्धन के अनुपालन के लिए उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट, प्रस्तुत की गई कोई घोषणा यदि कोई हो, गलत पाई जाती है, तब ऐसा आयातकर्ता ऐसे माल के मूल्य पर जिस के सम्बन्ध में ऐसा उल्लंघन या अननुपालन हुआ है या गलत घोषणा प्रस्तुत की गई है, धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित

पूर्ण दर पर संगणित कर के अतिरिक्त, इस अधिनियम की धारा 8 के निबन्धनों के अनुसार ब्याज संदत्त करने का दायी होगा :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व आयातकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।

अनुसूची
संशोधित
करने की
शक्ति ।

10. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में परिवर्धन या लोप या उसका अन्यथा संशोधन कर सकेगी और अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जाएगी।

नियम बनाने
की शक्ति।

11. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कर के उद्ग्रहण और संग्रहण को सुनिश्चित करने और साधारणतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिला कर पन्द्रह दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे, जो एक सत्र में या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, और यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखे गए हों, या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाए जाने चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उनके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची
(धारा 2(फ), 3(1), 7(1)(क) और 10 देखें)

क्रम संख्या	माल	छूट की शर्तें
1	2	3
1.	किसी व्यक्ति द्वारा या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा विक्रीत/जड़ी बूटियों या सैपलिन्ग सहित कृषि या बागवानी उपज जो स्वयं उगाई गई हो या ऐसी किसी भूमि पर उगाई गई हो जिसमें उसका कोई हित, चाहे स्वामी या भोग बन्धकदार या अभिधारी के रूप में या अन्यथा हो ।	—
2.	हस्त परिचालित और पशु द्वारा चलाए जाने वाले कृषि उपकरण ।	—
3.	विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए साधन और उपकरण ।	—
4.	पशुदाना (ऐनीमल फीड) और दाना परिपूरक अर्थात् मूर्गी दाना, पशुदाना (कैटलफीड), सुअर दाना, मछली दाना, मत्स्य भोजन, प्रान फीड, श्रिम्प फीड, और दाना परिपूरक के रूप में विक्रीत प्रसंस्कृत वस्तु के रूप में, घास, सुखी घास और भूसे सहित दाना परिपूरकों के रूप में प्रयोग के लिए आशयित खणिज मिश्रण सान्द्र ।	—
5.	कृषि प्रयोजनों में प्रयुक्त बांस से निर्मित वस्तुएं ।	—
6.	बान ।	—
7.	पुस्तिकें, पत्रिकाएं और जरनल्ज ।	—

1	2	3
8.	चरखा, अम्बूर चरखा; हथकरघे, हिमाचली हथकरघों से निर्मित वस्तुएं, हिमाचली हथकरघा शालें, टोपियाँ और हैंडस्पन यार्न और गांधी टोपी ।	—
9.	चारकोल ।	—
10.	धान, चावल और गेहूं से अन्यथा मोटा अनाज ।	—
11.	निरोध (कन्डोम) और गर्भनिरोधक ।	—
12.	हैंक में कपास सूत और हैंक में रेशमी सूत ।	—
13.	दही, लस्सी, बटर मिल्क और सेपरेटिड मिल्क ।	—
14.	मिट्टी के बर्तन (अनगलेजड) ।	—
15.	विद्युत उर्जा ।	—
16.	जलाने की लकड़ी ।	जब घरेलू उपयोग हेतु बेची जाए ।
17.	मछली जाल, मछली जाल का धागा और फीश सीडज ।	—
18.	भारत सरकार द्वारा मुफ्त में दिया जाने वाला अनाज ।	—
19.	ताजे फल ।	—
20.	ताजा दूध और पासच्युराइजड मिल्क ।	—
21.	फ्रेश प्लान्ट्स, सैपलिन्गज और फ्रेश फलावरज ।	—
22.	ताजी सब्जियां ।	—

1	2	3
23.	लहसुन और अदरक, हरी मिर्च, प्याज, आलू, शकरकंद, टेपिओका और उनके बीज ।	—
24.	कांच की चूड़ियां (जिनमें प्लास्टिक के खोल (शैल) और लाख की चूड़ियां भी हैं) ।	—
25.	ग्रेफाइट पेन्सिले, लिखने वाली चाक क्रेआन, स्केच, पेन, ड्राइंग कलर इरेजर (रबर), शॉर्पनर, फुटरूलज, रेखा गणित बाक्स, सियाही की टिक्कीयां, स्कूलों में प्रयुक्त किए जाने वाली अभ्यास और चित्रकला/पुस्तकें और विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली तख्तियां ।	—
26.	मानव रक्त (ह्यूमेन ब्लड) प्लाजमा ।	—
27.	हाथ के बनाए हुए स्वदेशीय संगीत वाद्य ।	—
28.	कुमकुम, बिन्दी, अल्टा और सिन्दूर ।	—
29.	पतल और डूने (जब कम्प्रेसड न हों) ।	—
30.	मांस, मछली, प्रॉन और अन्य जलीय उत्पाद जो संशोधित या डिब्बों में बेची फ्रोजन न हों; अण्डे और पशुधन तथा जानवरों के बाल । गई के सिवाए	—
31.	राष्ट्रीय झण्डा ।	—
32.	सरकारी खजानों द्वारा विक्रीत नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर; सरकार द्वारा विक्रीत पोस्टल वस्तुएं जैसे कि लिफाफे, पोस्ट कार्ड इत्यादि; रुपए का नोट जब उसे भारतीय रिजर्व बैंक को बेचा जाए और चैक चाहे अवद्ध या पुस्तिका के रूप में हों।	—

1

2

3

33. जैविक खाद ।

34. कच्ची उन (राँ बूल) ।

35. बीज ।

36. वीर्य जिसके अर्न्तगत जमा हुआ वीर्य भी है ।

37. काँकून और कच्चा रेशम देने वाला रेशम का कीड़ा ।

38. कच्चा हरा नारियल ।

39. तडी, नीरा और अरक ।

40. अनब्रान्डड ब्रेड ।

41. अन प्रोसेसडज और अनब्रान्डड साल्ट (नमक) ।

42. निम्नलिखित से अन्यथा जल-----

(i) ऐओरेटिड, मिनरल, डिसटिलड, मेडिसिनल,
आयोनिक, बाटरी, डिमिनरलाईन्ड वाटर और

(ii) बंद डिब्बों में बेचा जाने वाला जल ।

22.

43. लिखने में प्रयुक्त होने वाली स्लेट और स्लेटियां ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

स्थानीय क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए अतिरिक्त संसाधनों को संचालित •(जुटाने) करने की दृष्टि से, स्थानीय क्षेत्रों में, उपभोग या उपयोग के लिए कतिपय माल और ऐसे क्षेत्रों में उपयोग या विक्रय के लिए मोटर यानों के प्रवेश पर कर का उदग्रहण करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए नया विधान अधिनियमित करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

रंगीला राम राव,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला:

तारीख 2005

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 3 और 4 उपभोग या उपयोग के लिए स्थानीय क्षेत्रों में माल के, अनुसूची में विनिर्दिष्ट के सिवाय, प्रवेश और क्रमशः उपयोग या विक्रय के लिए मोटर यानों के प्रवेश पर, कर के उद्ग्रहण का प्रस्ताव करते हैं। विधेयक के उपबन्धों के अधिनियमित होने पर, प्रतिवर्ष लगभग पन्द्रह करोड़ रुपये की आय होनी सम्भाव्य है। विधेयक के उपबन्ध, अधिनियमित किये जाने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा कोई अतिरिक्त व्यय उपगत किए बिना, प्रशासित किए जाएंगे।

प्रत्यायोजित विधान सम्बंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 11 राज्य सरकार को इस विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य प्रकृति का है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें।

(आबकारी एवं कराधान विभाग नस्ति संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(6)4/2005)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र विकास कर विधेयक, 2005 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र विकास कर विधेयक, 2005.

हिमाचल प्रदेश राज्य के किसी स्थानीय क्षेत्र में उपयोग या विक्रय के लिए मोटर यान तथा उसमें उपयोग या उपभोग के लिए अन्य माल के प्रवेश पर कर का उद्ग्रहण तथा संग्रहण करने तथा उनसे सम्बद्ध या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

रंगीला राम राव,
प्रभारी मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि) ।

शिमला:
तारीख.....2005.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 13 of 2005.

THE HIMACHAL PRADESH LOCAL AREA DEVELOPMENT TAX BILL, 2005

(As introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

to provide for levy and collection of tax on the entry into a local area of the State of Himachal Pradesh, of motor vehicles for use or sale, and of other goods for use or consumption, therein and matters incidental thereto and connected therewith.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follows:—

CHAPTER-1 PRELIMINARY

Short title
and
commence-
ment.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Local Area Development Act, 2005.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context, —

- (a) “**Act**” means the Himachal Pradesh Local Area Development Act, 2005;
- (b) “**assessee**” means a person by whom tax is payable under this Act;
- (c) “**bring goods into a local area**” means causing the entry of goods into a local area by bringing them inside the local area or causing the goods to be brought inside the local area from any place outside the local area;
- (d) “**bring motor vehicle into a local area**” means causing the entry of motor vehicle into a local area by

bringing it inside the local area or causing it to be brought inside the local area from any place outside the local area;

(e) **“business”** includes, —

(i) any trade, commerce, manufacture, works contract, leasing or any adventure or concern in the nature of trade, commerce, manufacture, works contract or leasing, whether or not, such trade, commerce, manufacture, works contractor, leasing, adventure or concern is carried on regularly and with a motive to make gain or profit and whether or not any profit accrues therefrom; and

(ii) any transaction in connection with or incidental or ancillary to such trade, commerce, manufacture, works contract, leasing, adventure or concern;

(f) **“Commissioner”** means the Commissioner appointed under sub-section (1) of section 3 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005;

(g) **“entry of goods into a local area”** means taking or bringing goods into a local area from any place outside the State or from any place inside any other local area in the State;

(h) **“entry of a motor vehicle into a local area”** with all its grammatical variations and cognate expressions means entry of motor vehicle into a local area from any place outside it for use or sale therein;

(i) **“goods”** means all kinds of the movable property and includes livestock;

(j) **“goods carrier”** means any kind of vehicle of transport of goods including pipeline, motor vehicle, boat, push cart, animal drawn cart, tractor-trailer and the like;

(k) **“gross turnover”** used in relation to an importer with

reference to a period of time means the aggregate value of goods which the importer brings or receives on the entry of such goods into a local area during the given period;

- (l) **“importer”** means any person who, in the course of business, whether on his own account or on account of a principal or any other person, brings any goods into or receives or is entitled to receive any goods on their entry into a local area and includes a casual importer;

Explanation.— When a consignee does not take delivery of goods upon its entry into a local area, and such goods are sold under the provisions of any law, the buyer who takes delivery of such goods upon the goods being sold shall be deemed to be the importer thereof.

- (m) **“importer of a motor vehicle”** means a person who brings a motor vehicle into a local area from any place outside the local area for use or sale therein and who owns the motor vehicle at the time of its entry into a local area and includes a person who owns the motor vehicle at the time of its registration in the State under the Motor Vehicles Act 1988; 59 of 1988.
- (n) **“local area”** means an area within the limits of a Municipal Corporation established under the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, or a municipality established under the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 or a Cantonment Board established under the Cantonment Act, 1924, or the area falling in any other local bodies constituted under the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 or any other local authority constituted or continued under any law for the time being in force or any other area so notified by the State Government; 12 of 1994.
13 of 1994.
2 of 1924.
4 of 1994
- (o) **“manufacturer”** means a person who carries on business of manufacturing or processing of goods, whether wholly or partly;
- (p) **“motor vehicle”** means any vehicle registered or liable to be registered under the Motor Vehicles Act, 1988; 59 of 1988

- (q) **“place of business”** means any place where any importer is doing business and includes—
- (i) any warehouse, godown or other place where the importer stores or processes his goods;
 - (ii) any place where the importer produces or manufactures goods;
 - (iii) any place where the importer keeps his books of accounts; and
 - (iv) any place where the importer carries on business through an agent (by whatever name called), the place of business of such agent;
- (r) **“prescribed”** means prescribed by the rules made under this Act;
- (s) **“purchase value of a motor vehicle”** means the value of motor vehicle as ascertained from the invoice and includes the value of accessories fitted to the vehicle, insurance, excise duty, countervailing duties, sales tax, transport fee, freight charges and all other charges incidentally levied on the purchase of a motor vehicle:

Provided that if purchase value of a motor vehicle is not ascertainable on account of non availability or non-production of invoice or when the invoice produced is proved to be false or if the motor vehicle is acquired or obtained otherwise than by way of purchase, then the purchase value of a motor vehicle shall be the market value of a motor vehicle:

- (t) **“receive any goods”** means to take delivery or possession of any goods, whether actual or constructive, or cause the goods to be received by any other person;
- (u) **“sale tax”** means the tax leviable under the Central Sales Tax Act, 1956 and the tax levied under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, as the case may be;

- (v) **"Schedule"** means a Schedule appended to this Act;
- (w) **"State"** means the State of Himachal Pradesh;
- (x) **"State Government"** means the Government of Himachal Pradesh;
- (y) **"tax"** means the tax leviable under this Act;
- (z) **"taxable goods"** means the goods other than the goods specified in Schedule;
- (za) **"turnover"** used in relation to any assessee means the aggregate of the value of goods which the assessee brings or receives in any local area for consumption or use therein during any given period and which is determined in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder;
- (zb) **"value of the goods"** means the purchase value of such goods, that is to say, the purchase price at which an importer has purchased the goods inclusive of charges borne by him as cost of transportation, packing, forwarding and handling charges, commission, insurance, taxes, duties and the like or if such goods have not been purchased by him, the prevailing market price of such goods in the local area;
- (zc) **"works contract"** means any agreement for—
 - (i) the construction, fitting out, improvement, maintenance or repair of any building, road, bridge or any other immovable property, or
 - (ii) manufacture, processing, fabrication, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repair, conversion or commissioning of any movable property, for cash, deferred payment or other valuable consideration; and
- (zd) **"Year"** means the financial year.

CHAPTER-II LEVY OF TAX

3. (1) There shall be levied and collected a tax on the entry Levy of tax.
into a local area, of all goods except those specified in Schedule, for
consumption or use therein, at such rates not exceeding the rates of
12 of 2005. tax leviable under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005,
as may, by notification, be specified by the State Government, and
different rates may be specified in respect of different goods or different
classes of goods or different local areas.

(2) The tax levied under sub- section (1) shall be paid by the
importer:

Provided that an importer shall not be liable to pay tax so long
as the aggregate value of taxable goods, he brings into or receives on
their entry into any local area does not, in a year, exceed twenty lakhs
rupees or such other sum as the State Government may, by notification,
specify:

Provided further that an importer who has once become liable
to pay tax under this Act shall continue to be so liable until the expiry of
three consecutive years during each of which the aggregate value of
any taxable goods he brings into or receives on their entry into any local
area does not exceed the amount specified in the first proviso.

Explanation.—Where the goods are received on its entry into a
local area by a person other than an importer, the importer, if any, who
further receives the goods from such person shall be deemed to have
received the goods on entry into the local area.

(3) The tax shall be levied, assessed and collected in such
manner, as may be prescribed.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no
tax shall be levied on the notified goods imported by a dealer registered
of 2005. under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, who brings
such goods into any local area for the purpose of re-sale in the State or
during the course of *inter-State* trade or commerce:

Provided that if any such dealer, after importing the notified
goods for the purpose of re-sale, consumes such goods in any form or

deals with such goods in any other manner except reselling the same, he shall forthwith notify the assessing authority.

Special provisions of levy of tax on the motor vehicles.

4. (1) Notwithstanding anything contained in section 3 of this Act, there shall be levied and collected a tax on the entry of a motor vehicle into a local area for use or sale therein:

Provided that such motor vehicle is liable for registration or assignment of a new registration mark in the State under the Motor Vehicles Act, 1988:

59 of 1988

Provided further that no tax shall be levied and collected in respect of a motor vehicle which was registered in any Union Territory or any other State under the Motor Vehicles Act, 1988, for a period of fifteen months or more before the date on which it is registered in the State under that Act.

59 of 1988

(2) The tax shall be levied on purchase value of a motor vehicle at the rate equal to the difference between the sales tax rate applicable in the State and the sales tax or the central sales tax rate charged on the sale of the motor vehicle in the invoice relating to the purchase of the vehicle:

Provided that the sales tax rate applicable in the State for the purpose of this section shall be taken as on the date mentioned in the invoice relating to the purchase of the motor vehicle:

Provided further that if no invoice in respect of purchase of the motor vehicle is produced or if the invoice does not show the rate of sales tax or central sales tax, as the case may be, charged, then the tax rate applicable under this section shall be the rate of sales tax applicable in the State on the date of assessment.

Exemption of tax in certain circumstances.

5. Where any person brings a motor vehicle into a local area for his personal use within a period of fifteen months from the date of its registration in any Union Territory or any other State under the Motor Vehicles Act, 1988, and that such entry is occasioned as a result of shifting the place of his residence from such Union Territory or State into this State, Commissioner may, by order in writing, on application made to him in this regard, exempt such person from the payment of entry tax on entry of such vehicle subject to the production of proof.

59 of 1988

6. Every importer, who is liable to pay tax under sub-section (2) of section 3 of this Act, shall be liable to be registered under this Act, in such manner, on payment of such fee and within such period, as may be prescribed: Registration.

of 2005. Provided that if such importer is registered under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, he shall be deemed to have been registered under this Act.

CHAPTER-III RETURN, ASSESSMENT, PAYMENT, RECOVERY AND COLLECTION OF TAX

7. (1) In calculating the turnover liable to tax for a period, an importer may deduct from his gross turnover of goods purchased during that period,— Deductions from gross turnover.

- (a) the value of goods specified in Schedule;
- (b) the value of goods which have, without use or consumption, been delivered outside the local area;
- (c) the value of goods which have been subjected to tax once under this Act, either as such or in some other form;
- (d) the value of goods on which sales tax has been paid or has become payable to the State;
- (e) the value of plant, machinery, equipment and tools, brought or received on lease for use in manufacture or processing of goods;
- (f) the value of goods brought or received in a local area for resale or for use or whether as such or in different form, lying with him in the local area, except when the certificate of registration issued under this Act is cancelled:

Provided that the value of goods deducted under this clause shall, except when the certificate of registration issued under this Act is cancelled, form part of the turnover for the period immediately succeeding:

Provided further that the value of plant, machinery, equipment and tools, for use in manufacture or processing of goods, if forming part of the turnover, may form part of the losing stock, if capitalised; and

(g) the value of such other goods, as may be prescribed.

Explanation.—For the purpose of this sub-section, deduction of value of only such goods shall be admissible which forms part of gross turnover of the importer and if value of certain goods have been deducted under one clause, then, it shall not be deducted under any other clause.

(2) The deductions claimed under sub-section (1) shall be subject to the production of such proof in such form and in such manner, as may be prescribed. The Assessing Authority may ask for any relevant evidence to satisfy itself about the genuineness and the correctness of the proof furnished.

The
authorities
and admini-
stration of
tax.

8. Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the authorities for the time being empowered under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, to assess, re-assess, collect and enforce payment of tax, including any interest or penalty payable by a dealer, shall assess, reassess, collect and enforce payment of tax including any interest or penalty payable by an importer under this Act, as if, the tax or interest or penalty payable by such importer under this Act, is a tax under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, and for this purpose they may exercise all or any of the powers they have under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, and all the provisions of that Act including the provisions relating to registration, security, payment of tax and returns, payment of interest, prohibition against collection of tax in certain cases, assessment of tax, re-assessment of tax, non-application of limitation for completion of assessment or re-assessment of tax, tax and penalty recoverable as arrears of land revenue, tax, penalty and interest to be the first charge on the property, special mode of recovery, refund, accounts, production and inspection of books, documents and accounts, survey, establishment of check-post and barrier and inspection of goods in transit, registration and submission of returns by carrier of goods and agent of transport companies, assessee etc. permitted to attend through authorised agent, power to call for information, delegation of powers, transfer of business, liability to pay tax by a partitioned Hindu family, dissolved firms etc., liability of the legal heirs to pay tax, bar of certain proceedings, appeal, revision, rectification of mistakes, revision to the

12 of 2005.

A.

High Court, powers of authorities to take evidence on oath, offences and penalties, compounding of offences, cognizance of offences, directors of defaulting companies to be liable to pay tax, disposal of certain property, indemnity, returns etc. to be confidential, persons appointed to be public servants, power to seek assistance from police and other officers and burden of proof, shall apply *mutatis mutandis*.

(2) Subject to the provisions of sub-section (1), in the case of an importer other than a dealer, the assessment, payment, enforcement and collection of tax shall be such as may be prescribed.

(3) All the provisions relating to offences and penalties (including provisions relating to penalties in lieu of the prosecution for an offence, or in addition to the penalties or punishment for an offence) and the provisions relating to levy or charging of interest under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 shall, with necessary modifications, apply in relation to the assessment, re-assessment, collection and the enforcement of any tax required to be collected under this Act or in relation to any process connected with such assessment, re-assessment, collection or enforcement of payment, as if, the tax under this Act were a tax under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005.

9. (1) The State Government may, if in its opinion it is necessary in the public interest so to do, by notification, subject to such restrictions and conditions and for such period as may be specified in the notification, exempt or reduce the tax payable by any class of importer under this Act.

Power of the State Government to exempt or reduce tax.

(2) Where any restriction or condition specified in the notification issued under sub-section (1) is contravened or is not observed by an importer or where a declaration, if any, specified in the said notification for the observance of any condition or restriction imposed therein, furnished, is found to be wrong, then such importer shall, in addition to tax calculated at the full rate, notified under sub-section (1) of section 3, on the value of such goods in respect of which such contravention or non-observance has taken place or a wrong declaration has been furnished, be liable to pay interest in terms of section 8 of this Act:

Provided that before taking any action under this sub-section, the importer shall be given a reasonable opportunity of being heard.

Power to
amend
Schedule.

10. The State Government may, by notification, add to or, delete from or, otherwise, amend the Schedule and there upon the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.

Power to
make rules.

11. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules consistent with this Act, for securing the levy and collection of tax and generally for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are made, before the Legislative Assembly, while it is in session, for a total period of fifteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if, before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the Assembly agrees in making any modifications in the rules or the Assembly decides that the rules should not be made, such rules shall have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be. However, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything done earlier under that rule.

SCHEDULE

[See sections 2(v), 3(1), 7 (1) (a) and 10]

Sl, No.	Goods	Conditions of exemption
1	2	3
1.	Agriculture or horticulture produce, including herbs or saplings or trees sold by a person or a member of his family, grown by himself or grown on any land in which he has an interest whether as owner or as usufructuary mortgagee or as tenant or otherwise.	—
2.	Agricultural implements manually operated or animal driven	—
3.	Aids and implements used by handicapped persons	—
4.	Animal feed and feed supplements, namely processed commodity sold as poultry feed, cattle feed, pig feed, fish feed, fish meal, prawn feed, shrimp feed and feed supplements and mineral mixture concentrates, intended for use as feed supplements including grass, hay and straw.	—
5.	Articles made of bamboo-wood used for agricultural purposes.	—
6.	Baan	—
7.	Books, periodicals and journals	—
8.	Charkha, Ambar Charkha; handlooms, Himachali handloom articles, Himachali handloom shawls, caps and handspun yarn, and Gandhi Topi.	—
9.	Charcoal	—
10.	Coarse grains other than paddy, rice and wheat	—
11.	Condoms and contraceptives	—
12.	Cotton yarn in hank and silk yarn in hank	—

1	2	3
13.	Curd, lassi, butter milk and separated milk	—
14.	Earthen pots (unglazed)	—
15.	Electric Energy	—
16.	Fire wood	When sold for domestic use
17.	Fishnet, fish fabrics and fish seeds	—
18.	Foodgrains supplied free of cost by the Government of India	—
19.	Fresh fruits	—
20.	Fresh milk and pasteurised milk	—
21.	Fresh plants, sapling and fresh flowers	—
22.	Fresh vegetables	—
23.	Garlic, ginger, green chillies, onions, potatoes, sweet potatoes, tapioca and their seeds.	—
24.	Glass bangles (including plastic shell and lac bangles)	—
25.	Graphite pencils, writing chalk, crayons, sketch, pens, drawing colour eraser, sharpener, footrules, geometry boxes, ink tablets, exercise and drawing books of the type used in schools and takhties used by students.	—
26.	Human blood and blood plasma	—
27.	Indigenous handmade musical instruments	—
28.	Kumkum, bindi, alta and sindur	—
29.	Leaf plates and leaf-cups (when not compressed)	—
30.	Meat, fish, prawn and other aquatic products when not cured or frozen; eggs and livestock and animal hair.	Except when sold in sealed containers

1	2	3
31.	National flag	—
32.	Non-Judicial stamp paper sold by the Government Treasuries; postal items like envelope, postcard etc. sold by the Government; rupee note when sold to the Reserve Bank of India and cheques, loose or in book form.	—
33.	Organic manure	—
34.	Raw wool	—
35.	Seeds	—
36.	Semen including frozen semen	—
37.	Silk worm laying cocoon and raw silk	—
38.	Tender green coconut	—
39.	Toddy, Neera and Arak	—
40.	Unbranded bread	—
41.	Unprocessed and unbranded salt	—
42.	Water other than —	—
	(i) aerated, mineral, distilled, medicinal, ionic, battery, demineralised water, and	—
	(ii) water sold in sealed container	—
43.	Writing slate and slate pencils	—

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to mobilise additional resources for integrated development of the local areas, it has been decided to levy a tax on the entry of certain goods into local areas for consumption or use and motor vehicles for use or sale in such areas. This has necessitated the enactment of a new legislation.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

RANGILA RAM RAO,
Minister-in-Charge.

SHIMLA:

THE 2005

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 3 and 4 of the Bill proposes to levy a tax on the entry into a local area of goods except those specified in Schedule, for consumption or use and on the entry of a motor vehicle into a local area for use or sale respectively. The provisions of the Bill, when enacted, are likely to yield about Rs.15 crores per annum. The provisions of the Bill, when enacted, will be administered through the existing Government machinery without incurring extra expenditure.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 11 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of the Act. The proposed delegation of powers are essential and normal in character.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(Excise and Taxation Department File No. EXN-F(6) 4/2005)

The Governor, Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Local Area Development Tax Bill, 2005, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the said Bill in the State Legislative Assembly.

THE HIMACHAL PRADESH LOCAL AREA DEVELOPMENT TAX BILL, 2005

A
BILL

to provide for levy and collection of tax on the entry into a local area of the State of Himachal Pradesh, of motor vehicles for use or sale, and of other goods for use or consumption, therein and matters incidental thereto and connected therewith.

RANGILA RAM RAO,
Minister-in-Charge.

SURINDER SINGH THAKUR,
Secretary (Law).

SHIMLA:

The 2005